Central Water Commission
WSE Dte.,
****

West Block II, Wing No-4
R. K. Puram, New Delhi – 66.

Dated 06.03.2019

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings will be uploaded on the CWC website.

6/3/2019
SPA (Publicity)

Encl: As stated above.

Deputy Director, WSE Dte. 06/03/2019

Director, WSE Dte. 06/03/2019

O/C

For information to

Chairman CWC, New Delhi

Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

News item/letter/article/editorial Published on 06.03.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times ✓

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

TERI signs MoU with WAPCOS on power, water, and infra (Economic Times)

The Energy and Resources Institute (TERI) today announced it has signed an agreement with WAPCOS, a consulting firm, under the aegis of Ministry of Water Resources, to pursue opportunities in areas of power, water, and infrastructure development.

According to the memorandum of understanding (MoU), both TERI and WAPCOS will work on hydro-power-energy-climate change nexus; Water Security and Integrated Water Resources Management; water use efficiency in various sectors; water conservation and augmentation; urban and rural water demand and supply management; green infrastructure for smart cities, and climate resilient infrastructure in water sector.

TERI said it has conducted an analysis of the water-energy nexus and found the energy sector, specifically thermal power plants, is a guzzler of water as a resource. With India experiencing 6-8 per cent growth in electricity consumption every decade since 1980, this usage level is expected to increase.
TERI's studies have shown ways to reduce water footprint of operations, products.

News item/letter/article/editorial Published on 06.03.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi) ✓
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

बारिश और मौसम के बदलते रिश्तों में मानसून

4-6

पूरी दुनिया में मौसम चक्र जिस तरह बदल रहा है, उसमें मानसून की भविष्यवाणी कई सवाल खड़े कर रही है।

अभिषेक कुमार सिंह
वरिष्ठ लेखक

जब फरवरी और मार्च के महीने में भी बारिश हर कुछ दिन बाद बरस रही है और वेस्टर्न डिस्टरबेंस खबरों में लगातार छाया हुआ है, मानसून को लेकर एक बार फिर राहत देती भविष्यवाणियां सामने आ गई हैं। निजी एजेंसी स्काईमेट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस साल जून से सितंबर के बीच चार महीने की अवधि में सामान्य मानसूनी वर्षा होगी। इसके मुताबिक इससे खेती में लाभ होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। अत्यधिक बारिश के आसार काफी कम हैं। हालांकि इस दौरान सूखे की आशंका नहीं रहेगी पर दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। अक्सर इस बात पर राहत जताई जाती है कि अगर मानसून ठीकठाक बीत रहा है तो देश की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) पर कोई नकारात्मक असर पड़ने की आशंका भी नहीं रहती है। मानसून में बादल खूब बरसेंगे तो फसल अच्छी होगी, ग्रोथ रेट तेज भागेगी। बहुत सी कंपनियां इसी भविष्यवाणी के आधार पर अपने मुनाफे का अनुमान लगाती हैं। सूखे की आंशका न रहने के कारण सरकारें तो राहत की सांस लेती ही हैं। विडंबना यह है कि इतना पहले की गई भविष्यवाणी बहुत भरोसेमंद नहीं होती।

तमाम उपग्रहों और सुपर कंप्यूटरों के संजाल के बावजूद मौसम और मानसून के अंदाज को सौ फीसदी सही समझ पाना बेहद मुश्किल है। चाहे जितनी सटीक भविष्यवाणी का दावा किया जाये, पर सच यह है कि मानसून के दौरान बारिश और उसके पैटर्न में थोड़ी-बहुत ऊंच-नीच या कमी-बेशी का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए नीतियां बनाते समय या भविष्यवाणी के आधार पर राहतों का आकलन तय करते समय इस उतार-चढ़ाव के लिए स्पेस रखना जरूरी है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों की वजह से पूरी दुनिया का मौसमी-चक्र तेजी से बदल रहा है। अगर इन बातों को हाशिये पर रखा जाएगा और इनके आधार पर तैयारियां नहीं की जाएंगी, तो मानसून पर हमारी डगमगाती निर्भरता कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। इसके कई और पहलू हैं, जो साबित करते हैं कि मानसून जैसी बारिशों से रिश्ता अब टूट की कगार पर है। जैसे, कई देशों ने ऐसी फसलों पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, जिनके लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। उधर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों में अतिक्रमण के चलते बारिश अपना रास्ता बदल रही है।

भारत में ही अब तक जो उत्तर-पूर्वी इलाका धुआंधार बारिश के लिए जाना जाता था, दावा है कि आगे चलकर ये इलाके सूखा झेलेंगे और अपने सूखेपन के लिए मशहूर देश के मध्य-पश्चिमी हिस्से जबर्दस्त नमी के लिए जाने जाएंगे। आईआईटी मुंबई बारिश के 112 साल के आंकड़ों का हिसाब लगाकर पिछले वर्ष 2018 में बता चुकी है कि देश के कुल 632 में से 238 जिलों में बरसात का पैटर्न बदल चुका है। बदले हुए पैटर्न को राजस्थान और गुजरात में भी देखा जा सकता है, जहां 1901 से 2013 के बीच राजस्थान में नौ प्रतिशत तो गुजरात में 26.2 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों प्रदेशों में सौ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान बारिश के कारण गंवाई है। अमेरिका स्थित

तकनीक के विकास, तमाम उपग्रहों और सुपर कंप्यूटरों के बावजूद मौसम के अंदाज को समझना अभी भी काफी मुश्किल है।

मेसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने एक शोध में बताया कि बीते 15 सालों में भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में अच्छा पानी बरसा है, लेकिन इसका जोर उन इलाकों में ज्यादा है, जो हाल तक सूखे रहते थे। साफ है कि मानसून के इस नए ट्रेंड को ध्यान से समझने और प्रभावित इलाकों के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है क्योंकि इसी दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड जैसे ज्यादा बारिश वाले राज्यों में हर दूसरे-तीसरे साल सूखे की नौबत आ रही है और किसान अपनी सूखी फसलों का मुआवजा मांगने लगे हैं। पर क्या वास्तव में एक खेती प्रधान अर्थव्यवस्था इस दौर में पहुंच गई है कि हम मानसून से अपना रिश्ता खत्म घोषित कर दें? हम इस नतीजे पर एकदम भले न पहुंचना चाहें, पर यह सच है कि मानसून में अब पहले की तरह आशंकित करने वाले तत्व नहीं रहे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

News item/letter/article/editorial Published on 06.03.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi) ✓

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

6 हजार करोड़ का पैकेज फिर भी दूर नहीं हुआ सूखा

पैकेज के वैकल्पिक उपाय भी लचर

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार बुंदेलखंड के 13 सूखा प्रभावित जिलों के लिए अब तक विशेष पैकेज पर 6,250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, लेकिन इसमें से अधिकांश हिस्सों पर अब भी सूखे की चपेट में आने का संकट बना हुआ है। पैकेज के तहत किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका के उपाय भी नाकाफी साबित हुए हैं। यह खुलासा अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन 'टेरी' और 'चीति आयोग' के साझा अध्ययन में सामने आया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पूर्व सचिव और अब टेरी के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ निदेशक एस.के. सरकार 'पत्रिका' से बातचीत में कहते हैं कि बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज के प्रभाव के इस समीक्षात्मक आकलन में कई कमियां सामने आई हैं। इनका कहना है कि बहुत से उपाय इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनकी ठीक से निगरानी नहीं हुई और

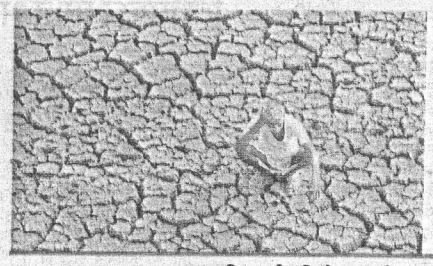

इस तरह बदल सकती है तस्वीर

इस इलाके के लिए रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। इसके मुताबिक इतने बड़े स्तर पर बदलाव के लिए जरूरी है कि वॉटरशेड आधारित फार्मूला अपनाया जाए। विभिन्न तकनीक का उपयोग कर सूखा प्रभावित क्षेत्र का जलविज्ञान संबंधी और जल-भूमिविज्ञान संबंधी प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाए। इसी तरह पानी की जरूरत की पूरे इलाके के साथ ही जिलेवार मॉडलिंग की जाए। इसमें मौजूदा जरूरत के साथ ही भविष्य की मांग का पैटर्न भी शामिल हो। टेरी के विशेषज्ञों के मुताबिक परियोजना के लाभार्थियों की बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए। साथ ही जल स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं जो स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को आयोजित कर सकें।

प्रमुख सुझाव

- मौजूदा और भविष्य की पानी की मांग का पैटर्न तैयार किया जाए
- परियोजना के लाभार्थियों की बैलेंस शीट तैयार की जाए
- स्थानीय स्तर पर गतिविधियां आयोजित करने के लिए जल स्वयं सहायता समूह बनाएं

सिंचाई परियोजनाओं का लाभ बहुत कम दूरी तक

इस रिपोर्ट में पाया गया है कि पैकेज के तहत मंझोली और छोटी सिंचाई परियोजनाएं तो शुरू की गईं लेकिन इनका फायदा एकदम पास के हिस्से में रहने वाले किसानों को ही मिल रहा है। इसी तरह चेक डैम और कुएं भी इस तरह बनाए गए हैं कि ये कुछ इलाकों में ही सिमित हैं।

सूचना तंत्र कमजोरी है। बुंदेलखंड के ये जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आते हैं। यह स्थिति दोनों ही राज्यों में देखी गई है।

70 फीसदी दुग्ध सहकारी समिति निर्जीव

लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका के लिए इस पैकेज के तहत दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गईं। लेकिन इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक काम नहीं कर रही हैं और इनसे दूध की कोई खरीद नहीं हो रही है। इस पैकेज के तहत खोले गए दूध प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर से लोगों की आमदनी बहुत कम बढ़ी है। इन इकाइयों में दूध से अन्य उत्पाद बनाने की सुविधा नहीं है।

News item/letter/article/editorial Published on 06.03.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express ✓
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Why the Brahmaputra needs long bridges

DE-6

ABHISHEK SAHA
GUWAHATI, MARCH 5

THE CABINET Committee on Economic Affairs last week approved the construction of a four-lane bridge over the Brahmaputra. It will be the country's longest, and will boost connectivity and commerce in the region.

How the bridge helps

At 19.28 km, it will connect Dhubri in Assam to Phulbari in Meghalaya. It is projected to reduce the travel distance between these two places from 205.3 km to 19.282 km, and travel time from 5 hours to 20 minutes.

"As of now, the only means of going directly from Dhubri to Phulbari is by boat. It takes approximately 3 hours, and while returning it takes 5 hours against the current. This will come down to 25-30 minutes at the most after the bridge comes up," Bikash Sarma, information and public relations officer of Dhubri district, told *The Indian Express*.

A Press Information Bureau (PIB) statement said the alignment will augment the transport network for the Northeast region, by providing the shortest link connecting western Meghalaya, as well as the southern NE states of Manipur, Mizoram and Tripura, with the rest of the country.

Brahmaputra again

The current longest road and rail-road bridges of the country are already over the Brahmaputra. The Dhola-Sadiya bridge (road) runs 9.15 km, and the Bogibeel bridge (rail-road) is 4.94 km.

The Brahmaputra, running 670 km in Assam, is extremely wide at some places. "It is the narrowest in Guwahati, say about 1 km, and the widest in Dibrugarh, over 15 km stretching to 20 km," Dulal Chandra Goswami, former head of environment studies at Gauhati University, said. "Assam is bisected by the Brahmaputra and it numerous tributaries. Naturally, people are handicapped when they have no means to cross the river. Bridges will be immensely helpful since distances will be reduced by hundreds of kilometres," Prof Goswami said.

Inaugurating the Bogibeel bridge in 2018, Prime Minister Narendra Modi had said three bridges over the Brahmaputra were completed in the last four-and-a-half years and another five were being built.

Construction

The bridge will be built under the North-East Road Network Connectivity Project with loan assistance from Japan International Cooperation Agency. The PIB statement said construction would cost Rs 3,548 crore, and the total capital cost would be Rs 4,997.04 crore. Construction is expected to be completed in approximately six years.

In December, Minister of State for Road Transport and Highways Mansukh Mandaviya had told Lok Sabha that construction was scheduled to be taken up during 2019-20.